विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में स्वीकृत किये गये मामलों सहित राज्यवार मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) आज की तारीख में कितने मामले स्वीकृति के लिए लम्बित हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Tax on agricultural income

59. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a number of Economists have suggested to impose tax on agricultural income from time to time;

(b) if so, details thereof;

(c) whether there is a proposal to tax agriculture income; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Tax Reforms commitee (1991) under the chairmanship of Prof. Chelliah had recommended levy of income tax in those cases of tax payers having agricultural income above Rs. 25,000/-, whose non-agricultural incomes are above the exemption limit. The committee had recommended obtaining the consent of the State Governments for enacting such a provision. Later another study group (1995) constituted by Central Board of Direct Taxes for reviewing the exemptions and concessions under Income Tax Act, 1961 was of the firm view that in order to widen the tax base and raise revenue for developmental programms, agricultural sector should be brought within the scope of Direct Taxes. Long back in 1972 also a Committee on Taxation of Agricultural Wealth and Incomes was constituted under the chairmanship of Dr. K.N. Raj. This committee also recommended for taxation of agricultural income under Direct Taxes.

(c) No, Sir.

(d) In view of the (c) above, question does not arise.

सरकार द्वारा ऋण लिया जाना

60. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से कर्ज लिया है;

(ख) यदि हां, तो वे स्त्रोत कौन-कौन से हैं तथा प्रत्येक स्त्रोत से कितना कर्ज लिया गया है; और

(ग) मार्च, 1999 तक देश पर विभिन्न स्त्रोतों से लिए जाने वाले कुल कर्ज की राशि का क्या अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) राजकोषीय घाटा, जो कुल व्यय (वापसी-अदायगी का निवल) और ऋण-भिन्न प्राप्तियों के बीच अंतर पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान अतिरिक्त उधार की आवश्यकताओं का द्योतक है, वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 91025 करोड़ रुपये रखा गया है। यह अतिरिक्त उधार बाजार ऋणों (48326 करोड़ रुपये), विदेशी सहायता (2337 करोड़ रुपये), लघु बचत स्कीमों (21640 करोड़ रुपये), भविष्य निधियों (5350 करोड़ रुपये), विशेष जमाराशियों (9495 करोड़ रुपये) और अन्य (3877 करोड़ रुपये) के माध्यम से जुटाने की योजना बनाई गई थी।

(ग) चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान दिनांक 27 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों में प्रतिबिंबित होंगे।

Reduction in budgetary deficit

61. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have of late taken any steps to ensure reduction in budgetary deficits which have been on an increase;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the results assessed?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) With the introduction of Ways and Means Advances system from 1.4.1997 for the Central Government, the concept of budgetary deficit has lost its relevance from the financial year 1997-98. However, Government would endeavour to contain the fiscal deficit, which represents the total additional borrowing